Q.1) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह PFRDA अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का प्रबंधन और नियमन करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह PFRDA अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।	PFRDA भारत का एक पेंशन नियामक है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का प्रबंधन और नियमन करता है तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को भी प्रशासित करता है।

Q.2) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह ऑडिटिंग पेशे की देखरेख करने वाला एक स्वतंत्र नियामक होगा।
2. इसमें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी।
3. इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किसी भी कंपनी की जांच करने की शक्ति होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.2) Solution (a)

- ऑडिट फर्में हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले जैसे विभिन्न कॉर्पोरेट घोटालों में कथित चूक के लिए जांच के दायरे में है।
- इस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- एनएफआरए का निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाया गया प्रमुख परिवर्तनों में से एक था।
- NFRA ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करेगा।

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
NFRA ऑडिटिंग पेशे की देखरेख करने वाला एक स्वतंत्र नियामक होगा। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड	इसमें सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होंगी।	इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, 1949 के तहत पंजीकृत ऑडिटर्स की जांच करने की शक्ति होगी

अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से सभी अधिकार लेगा।		

Q.3) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें

	समिति	अध्यक्ष
1	म्युनिसिपल बांड विकास समिति	सुजीत प्रसाद
2	प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति	जयंत आर वर्मा
3	द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति	टी वी मोहनदास पई

ऊपर दी गई कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.3) Solution (c)

युग्म 1	युग्म 2	युग्म 3
सत्य	**असत्य**	**असत्य**
इसकी अध्यक्षता सुजीत प्रसाद कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: a. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना। b. प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए जरूरी मामलों पर सेबी को सलाह देना। c. प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों के विनियमन से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देना। d. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए जारीकर्ताओं	इसका नेतृत्व टी वी मोहनदास पई कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: 1. भारत में प्राथमिक बाजार के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना। 2. प्राथमिक बाजार में प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए जरूरी मामलों पर सेबी को सलाह देना। 3. प्राथमिक बाजार में निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों के विनियमन से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देना।	इसकी अध्यक्षता जयंत आर वर्मा कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: 1. माध्यमिक बाजार में विकास की समीक्षा करना; 2. आसन्न परिवर्तनों को देखते हुए बाजार संरचना में परिवर्तन और सुधार के उपायों की सिफारिश करना; 3. बाजार की सुरक्षा, दक्षता, पारदर्शिता और अखंडता में सुधार के उपायों की सिफारिश करना; 4. लेनदेन लागत को कम करने के उपाय सुझाना; 5. यदि जोखिम प्रबंधन / मार्जिन प्रणाली में आवश्यक हो तो परिवर्तन की सिफारिश करना; 6. द्वितीयक बाजार में नियामक ढांचे में आवश्यकता होने पर परिवर्तन की सिफारिश करना;

(यानी नगर पालिकाओं) को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर सेबी की सिफारिश करना।		

Q.4) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. योजना का कार्यान्वयन निकाय भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) होगा
2. इसका उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
3. इस योजना के तहत, प्रति वर्ष 8% के लाभ की गारंटी दर के साथ एक सुनिश्चित पेंशन दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) उपरोक्त सभी

Q.4) Solution (d)

वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को आरंभ करने के लिए अपनी वास्तविक स्वीकृति दी है।

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना का कार्यान्वयन निकाय होगा।	इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।	इस योजना के तहत, प्रति वर्ष 8% के लाभ की गारंटी दर के साथ एक सुनिश्चित पेंशन दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, नॉमिनी के पास मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन का विकल्प होगा।

Q.5) 2018-19 में भारत को अपने एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित देशों को व्यवस्थित करें

1. अमेरीका
2. मॉरीशस
3. सिंगापुर
4. नीदरलैंड

सही कूट चुनें

a) 1-4-2-3
b) 4-1-3-2
c) 3-2-4-1
d) 4-1-2-3

Q.5) Solution (a)

भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) इक्विटी अन्तर्वाह 2018-19 में छह वर्ष में पहली बार टेलीकॉम, फार्मास्युटिकल और पावर में विदेशी फंडों की अधिक गिरावट के साथ नीचे गया है।

मंगलवार को उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 1% घटकर 44.4 बिलियन डॉलर 2018-19 हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 44.8 बिलियन डॉलर था।

एफडीआई प्रवाह दूरसंचार में 56% गिरकर $ 2.7 बिलियन तथा 74% फार्मास्यूटिकल्स में गिरकर 266 मिलियन डॉलर हो गया है।

इसके अलावा, सिंगापुर ने मॉरीशस को एफडीआई के साथ विदेशी निवेश के शीर्ष स्रोत के रूप में प्रतिस्थापित किया, जो मॉरीशस से $ 8.1 बिलियन की तुलना में $ 16.2 बिलियन के साथ वर्ष के दौरान मॉरिशस से दोगुना है।

नीदरलैंड (3,870 मिलियन डॉलर), इसके बाद यूएसए (3,139 मिलियन डॉलर) और जापान पांचवें (2,965 मिलियन डॉलर) स्थान पर रहा

Q.6) निम्नलिखित में से किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 प्रकाशित की है?

a) अंकटाड (UNCTAD)
b) विश्व आर्थिक मंच
c) विश्व बैंक
d) UNDESA

Q.6) Solution (a)

विश्व निवेश रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों की निगरानी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश नीति के विकास का दस्तावेजीकरण करके नीति निर्माताओं का समर्थन करती है।

इस वर्ष की रिपोर्ट का नीति अध्याय अंतरराष्ट्रीय निवेश समझौतों के सुधार और नए उपायों का सर्वेक्षण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का निरिक्षण करता है।

समावेशी सतत विकास एक वैश्विक नीति वातावरण पर निर्भर करता है, जो सीमा पार निवेश के लिए अनुकूल होता है।

विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 वैश्विक एसईजेड परिदृश्य का अवलोकन प्रदान करता है तथा सतत विकास अनिवार्यता, नई औद्योगिक क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन के बदलते पैटर्न द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के लिए मूलभूत चुनौतियों का प्रतिउत्तर देने के बारे में सलाह देता है।

Q.7) भारतीय संदर्भ में, छाया बैंकिंग (Shadow Banking) के घटकों में शामिल हैं

1. मुद्रा बाजार फंड (Money Market Funds)
2. क्रेडिट निवेश कोष (Credit investment Fund)
3. हेज फंड (Hedge Funds)
4. एनबीएफसी

सही कूट चुनें

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 3, और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.7) Solution (d)

भारतीय संदर्भ में छाया बैंकिंग

'छाया बैंकिंग प्रणाली' शब्द का पहली बार उपयोग 2007 में किया गया था तथा यह नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर संस्थाओं द्वारा किए गए बैंक जैसे कार्यों को संदर्भित करता है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB), यानी, 'क्रेडिट मध्यस्थता जिसमें संस्थाओं और गतिविधियों (पूरी तरह या आंशिक रूप से नियमित बैंकिंग प्रणाली से बाहर)' शामिल हैं, द्वारा अपनाया गया है और अधिक व्यापक परिभाषा, विश्व स्तर पर स्वीकार की गई है। इस परिभाषा के दो महत्वपूर्ण घटक हैं:

बैंकिंग प्रणाली के बाहर गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएँ या संस्थान जो परिपक्वता परिवर्तन की गतिविधियों जैसे 'बैंक' में संलग्न हैं, क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय उत्तोलन (financial leverage) का उपयोग करती हैं।

गैर-बैंक संस्थाओं के लिए धन के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में कार्य करने वाले प्रतिभूतिकरण, प्रतिभूतियों को उधार देने और रेपो लेनदेन जैसी गतिविधियाँ होती हैं। इस प्रकार, छाया बैंकों में ऐसी संस्थाएं शामिल होती हैं जो सीधे वित्तीय मध्यस्थता का संचालन करती हैं, जैसे कि वित्त कंपनियां या एनबीएफसी, तथा ऐसी संस्थाएं जो ऐसी संस्थाओं को म्युचुअल फंड जैसे वित्त प्रदान करती हैं। वैश्विक स्तर पर, छाया बैंकिंग संस्थाओं को व्यापक प्रमुखों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है

- मुद्रा बाजार फंड (Money Market Funds) ,
- क्रेडिट निवेश कोष
- हेज फंड
- वित्त कंपनियों का फंडिंग की तरह जमा स्वीकार करना
- क्रेडिट बीमाकर्ता, वित्तीय गारंटी प्रदाता
- प्रतिभूतिकरण वाहन (Securitisation vehicles)

छाया बैंकिंग संस्थान निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और प्रणाली में तरलता उत्पन्न करते हैं। हालांकि ये संस्थाएं बैंकों द्वारा दी जाने वाली पारंपरिक मांग जमा को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन वे व्यावसायिक बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करती हैं। तथा यह एक कारण था कि वे विदेश में विनियमन से बच गए हैं। छाया बैंकिंग प्रणाली 2008 में वित्तीय संकट से पहले अमेरिका में ऋण की पेशकश में नियमित बैंकिंग प्रणाली से आगे निकल गई थी।

Q.8) 'क्षेत्रक कोष' (Sector Funds) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. क्षेत्रक कोष, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं
2. क्षेत्रक कोष, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक जोखिम रखते हैं

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.8) Solution (b)

कथन 1	कथन 2

असत्य	सत्य
क्षेत्रक कोष (Sector funds) वे म्यूचुअल फंड होते हैं जो पूरी तरह से उन व्यवसायों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष उद्योग या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करते हैं। पहला कथन गलत है क्योंकि सेक्टर फंड्स क्लोज-एंड फंड होते हैं	चूंकि वे क्लोज-एंड फंड (closed ended funds) होते हैं, इसलिए उनके पास विविधीकरण का अभाव होता है, तथा वे विविध इक्विटी म्यूचुअल फंडों की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते है।

Q.9) भारत में पार्टिसीपेटरी नोट्स (Participatory Notes) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को RBI द्वारा पार्टिसीपेटरी नोट्स जारी किए जाते हैं।
2. पार्टिसीपेटरी नोट्स में निवेश करने वाली किसी भी इकाई को सेबी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.9) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट जारी किए जाते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स बड़े हेज फंड को उनकी पहचान बताए बिना उनके संचालन को पूरा करने में सक्षम बनाता है।	पी-नोट्स ने हाल ही में इस मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निधियों के विशाल प्रवाह के कारण महत्वपूर्ण बाजार का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाली किसी भी इकाई को सेबी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह पंजीकृत एफआईआई से खरीदी गई होती है

Q.10) भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले मुख्य विधान निम्नलिखित में से कौन से हैं?

1. सेबी अधिनियम, 1992
2. कंपनी अधिनियम, 1956
3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
4. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (Depositories Act)

सही कूट चुनें

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 3 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.10) Solution (d)

प्रतिभूति बाज़ार को नियंत्रित करने वाले चार मुख्य विधान हैं:

- सेबी अधिनियम, 1992 जो निवेशकों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए सेबी की स्थापना करता है;
- कंपनी अधिनियम, 1956, जो प्रतिभूतियों के निर्गमन, आवंटन और हस्तांतरण, तथा सार्वजनिक प्रस्तावों (public issues) में किए जाने वाले निर्गमन के संबंध में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए आचार संहिता निर्धारित करता है;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, जो स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रतिभूतियों में लेनदेन के नियमन का प्रावधान करता है; तथा
- डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 जो इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव और डीमैट सिक्योरिटीज के स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करता है।

Q.11) मुद्रा, सरकारी-प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव्स बाजारों में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य प्रदान करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शामिल है?

a) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL)
b) सेबी
c) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
d) भारतीय रिजर्व बैंक

Q.11) Solution (a)

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (Clearing Corporation of India Ltd- CCIL) की स्थापना अप्रैल, 2001 में मुद्रा, सरकारी-प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव्स बाजारों में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य को प्रदान करने के लिए की गई थी। गारंटीकृत समाशोधन और निपटान की शुरूआत से बाजार में दक्षता, पारदर्शिता, तरलता और जोखिम प्रबंधन / माप पद्धतियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ तथा साथ ही साथ, कम निपटान और परिचालन जोखिम, निपटान लागत पर बचत, आदि जैसे अतिरिक्त लाभ हुए हैं।

CCIL रूपए लाभ दर डेरिवेटिव के लिए गैर-गारंटीकृत निपटान भी प्रदान करता है तथा CLS बैंक के माध्यम से क्रास-मुद्रा लेनदेन को संभव करता है। CCIL के वित्तीय बाजार अवसंरचना के रूप में अपने कार्यों को संचालित करने वाले कड़े सिद्धांतों का पालन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2014 में एक योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (QCCP) के रूप में अपनी मान्यता के परिणामस्वरूप किया गया है। इसने वित्तीय संस्थानों को OTC डेरिवेटिव में उनके लेनदेन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक ट्रेड रिपोजिटरी भी स्थापित की है।

CCIL वित्तीय बाजार में विभिन्न भूमिकाओं को लेने के लिए वित्तीय क्षेत्र के स्थानांतरण प्रतिमानों के साथ वर्ष दर वर्ष विकसित हुआ है। अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्लीयरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से, सीसीआईएल ने विभिन्न बाजार खंडों में समझौतों के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पेश किए हैं। इसके अलावा, सीडीएसएल ने एनडीएस-ओएम को विकसित, कार्यान्वित और प्रबंधित किया है - आरबीआई के पास सरकारी-प्रतिभूतियों में निपटने के लिए बेनामी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है और ओटीसी समझौतों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ एनडीएस-कॉल मंच भी है जो कॉल में इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार की सुविधा देता है।

Q.12) विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है?

a) वित्त मत्रांलय
b) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
c) विदेश मंत्रालय
d) कारपोरेट कार्य मंत्रालय

Q.12) Solution (b)

भारत में कोई भी निवेश - या तो स्वचालित रूट के तहत जिसे आरबीआई से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है या सरकारी रूट के तहत, जिसे संबंधित मंत्रालयों / विभागों से एक खिड़की के माध्यम से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है - उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन के लिए विभाग (DPIIT) द्वारा प्रशासित विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफबी) से कर सकता है।

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal)

- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ताकि FDI अंतर्वाह को गति दी जा सके तथा देश में FDI अनुमोदन में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। FIFP ने मई, 2017 में FIPB का स्थान लिया।
- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) निवेशकों के लिए भारत सरकार का नया ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा देता है। यह पोर्टल उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
- यह पोर्टल उन अनुप्रयोगों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा जारी रखेगा जो अनुमोदन मार्ग से होते हैं। एफडीआई आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया करेगा।

Q.13) अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वे संस्थानों की तरह म्यूचुअल फंड हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों की भीड़ से पैसे की छोटी रकम जमा करके बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को सक्षम बनाते हैं
2. वे रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA)) द्वारा विनियमित होते हैं
3. InvITs केवल विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 1 और 2

Q.13) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएं हैं, जो अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश करने में सक्षम बनाती हैं, ताकि बुनियादी ढांचा में सीधे निवेश के लिए व्यक्तिगत निवेशकों की भीड़ से छोटी रकम जुटाई जा सके, ताकि यूनिट के आय का एक हिस्सा (व्यय में कटौती के बाद), InvITs के धारक, जो	भारत में प्रतिभूतियों के बाजार नियामक- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा InviTs का विनियमन किया जाता है। SEBI ने SEBI (Infrastructure Investment Trusts) विनियम, 2014 को 26 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया, जो भारत में InvITs के पंजीकरण और विनियमन के लिए	InvITs बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, या तो सीधे या एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के माध्यम से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, ऐसे निवेश केवल एसपीवी के माध्यम से हो सकते हैं।

पैसे में जमा हुए हैं, उन्हें लाभ का अंश वापस किया जा सके। InviTs के प्रकार दो प्रकार के InviTs को अनुमति दी गई है, एक जो मुख्य रूप से पूर्ण और राजस्व सृजन करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति है तथा दूसरी जिसमें पूर्ण / निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश करने की सुविधा है। जबकि पूर्व को अपनी इकाइयों की सार्वजनिक पेशकश करनी होती है, बाद वाले को अपनी इकाइयों के निजी प्लेसमेंट का विकल्प चुनना होता है। दोनों संरचनाओं को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है। चुनिंदा राज्य संचालित कंपनियों के विमुद्रीकरण के लिए अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी।	प्रावधान प्रदान करता है। InvIT का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की सुविधा प्रदान करना है। संरचना और परिचालनों में InvITs रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) से बहुत मिलते-जुलते हैं। InvITs संशोधित REITs हैं जिन्हें भारत में विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।	

Q.14) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भुगतान संतुलन देश के नागरिकों और संसार के बाकी हिस्सों के बीच लेनदेन की गणना करता है।
2. पूंजीगत खाते में बड़े बदलाव यह संकेत दे सकते हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए एक देश कितना आकर्षक है और विनिमय दरों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।
3. किसी देश के अधिशेष पूंजीगत खाते के ज़रिए उसकी परिसंपत्तियों के बढ़ते विदेशी स्वामित्व का संकेत मिलता है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 2

Q.14) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
भुगतान संतुलन (बीओपी) एक देश के निवासियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेनदेन को निर्दिष्ट समय अवधि के लिए संसार के बाकी हिस्सों के साथ होता है, जिसे	भुगतान संतुलन एक पूंजी खाते और एक चालू खाते से बना होता है - हालांकि एक संकीर्ण परिभाषा पूंजी खाते को एक वित्तीय खाते और एक पूंजी खाते में तोड़ देती है। लेखांकन में,	क्योंकि सभी लेन-देन शून्य से भुगतान राशि में दर्ज किए गए हैं, जो देश बड़े व्यापार घाटे (चालू खाता घाटे) में रहते हैं, परिभाषा के अनुसार बड़े पूंजी खाता अधिशेष

आम तौर पर एक वर्ष में रिकॉर्ड किया जाता है। भुगतान संतुलन (बीओपी), जिसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में भी जाना जाता है, सभी लेनदेन को संक्षेप में बताता है कि देश के व्यक्ति, कंपनियां और सरकारी निकाय देश के बाहर व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी निकायों के साथ लेनदेन को सारांशित करते हैं। इन लेनदेन में माल, सेवाओं और पूंजी के आयात और निर्यात के साथ-साथ विदेशी सहायता और प्रेषण जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं।	पूंजी खाता एक विशिष्ट समय में एक व्यापार के निवल मूल्य को दर्शाता है - और अन्यथा शेयरधारकों की इक्विटी के रूप में जाना जाता है। भुगतान संतुलन में परिवर्तन से देश के आर्थिक स्वास्थ्य के सापेक्ष स्तर और भविष्य की स्थिरता के बारे में कई साक्ष्य मिल सकते हैं। पूंजी खाता इंगित करता है कि कोई देश पूंजी का आयात या निर्यात कर रहा है या नहीं। पूंजी खाते में बड़े बदलाव यह संकेत दे सकते हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए एक देश कितना आकर्षक है और विनिमय दरों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।	भी रहने चाहिए - जिसका अर्थ है कि किसी देश के अधिशेष पूंजीगत खाते के ज़रिए उसकी परिसंपत्तियों के बढ़ते विदेशी स्वामित्व का संकेत मिलता है। एक बड़े व्यापार अधिशेष वाला देश पूंजी निर्यात कर रहा है, और पूंजी खाता घाटा हो रहा है - जिसका अर्थ है मुद्रा, देश से बाहर जा रही है।

Q.15) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपना अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है
2. भारत में पिछले 5 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार बढ़ा है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.15) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**असत्य**
एफडीआई आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है तथा देश के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक स्रोत है। सरकार ने एफडीआई पर एक निवेशक-अनुकूल नीति रखी है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों / गतिविधियों में स्वचालित मार्ग पर 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के कारण भारत में 2014-15 से 2018-19 तक पाँच वर्षों में कुल एफडीआई बढ़कर 286 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले पांच वर्षों में 189 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। USD 64.37 बिलियन, 2018-19 में FDI किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त किया गया सबसे अधिक निवेश है।	एक स्थिर और अनुमानित विनियामक शासन, एक बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत बुनियादी बातों के कारण, भारत पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बड़ी मात्रा को आकर्षित कर सका है, जोकि एफडीआई के रूप में प्राप्त 239 बिलियन अमरीकी डालर है। इस अवधि में एफडीआई नीति का तेजी से उदारीकरण भी देखा गया, जिससे अधिकांश एफडीआई स्वत: मार्ग से आने लगे। लेकिन एफडीआई लगातार नहीं बढ़ा है।

Q.16) शुद्ध अदृश्य (Net Invisibles) किसी निश्चित समय में किसी देश के अदृश्य निर्यात और आयात मूल्य के बीच का अंतर है। इस संदर्भ में, गैर-कारक आय का गठन कौन करता है

1. श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय आय

2. पूंजी पर अंतर्राष्ट्रीय आय
3. शिपिंग
4. बैंकिंग
5. पर्यटन

सही कूट चुनें

a) केवल 1, 2, 3 और 4
b) केवल 2, 3, 4 और 5
c) केवल 3, 4 और 5
d) उपरोक्त सभी

Q.16) Solution (c)

शुद्ध अदृश्य (Net Invisibles) एक निश्चित समय में किसी देश के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। अदृश्य योग्य में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, स्थानांतरण और प्रवाह की आय शामिल होती हैं। सेवा व्यापार में कारक और गैर-कारक आय दोनों शामिल हैं। कारक आय में उत्पादन के कारकों (जैसे श्रम, भूमि और पूंजी) पर शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आय शामिल है। गैर-कारक आय शिपिंग, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाओं आदि जैसे सेवा उत्पादों की शुद्ध बिक्री है।

Q.17) 'अर्थव्यवस्था के खुलेपन' (openness of an economy) के स्तर को, निम्न में से किस कारक द्वारा मापा जाता है?

a) विश्व जीडीपी में निर्यात और आयात का हिस्सा
b) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात
c) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भुगतान संतुलन
d) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार संतुलन

Q.17) Solution (b)

खुलेपन को किसी देश के माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के रूप में मापा जाता है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होती है। तो, विकल्प b सही है

व्यापार संतुलन का अर्थ है निर्यात - आयात है, इसलिए विवरण d गलत है।

Q.18) क्रय शक्ति समता (PPP) विनिमय दरों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि दो देशों में मुद्रास्फीति की दर शून्य है, तो उनकी पीपीपी विनिमय दरें स्थिर रहेंगी
2. पीपीपी विनिमय दर पर परिवर्तित होने पर दोनों देशों में सामान की कीमतें समान होंगी

उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.18) Solution (d)

मान लीजिए नॉमिनल विनिमय दर $ 1 = 70 है तथा भारत और अमेरिका सिर्फ पिज्जा का उत्पादन करते हैं

	भारत	यू.एस.
पिज्जा की कीमत	35	$ 1

पीपीपी विनिमय दर की गणना करने के लिए, हमें अमेरिका के साथ भारत में सामान की एक टोकरी की कीमतों की तुलना करने की आवश्यकता है।

भारत और अमेरिका में पिज्जा की कीमतों की तुलना करके उपरोक्त मामले में, हमें $ 1 = 35 रु मिलता है
तो, $ 1 = 35 पीपीपी विनिमय दर है। इसका तात्पर्य है कि भारत में जो भी 35 रुपये खरीद सकता है, यूएस में $ 1 खरीद सकता है यानी भारत में 35 रुपये की क्रय शक्ति यूएस में $ 1 की क्रय शक्ति के बराबर है।

इसलिए, अगर देशों में मुद्रास्फीति की दर अलग है, तो पीपीपी विनिमय दर बदल जाएगी। लेकिन अगर कोई मुद्रास्फीति नहीं है (कीमतें समान हैं) तो पीपीपी विनिमय दरें स्थिर रहेंगी।

तो, कथन 1 सही है।

जब हम US में पिज़्ज़ा की कीमत को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए PPP एक्सचेंज ($ 1 = 35 रु।) की दर का उपयोग करते हैं तो यह 1 US में 35 रु. होता है जो भारत में भी वैसा ही है।

तो, कथन 2 भी सही है।

Q.19) भारतीय संदर्भ में, रुपये के मूल्यह्रास (depreciation) का क्या अर्थ है?

a) विनिमय दर में वृद्धि जहां घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
b) विनिमय दर में वृद्धि जहां विदेशी मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में भारतीय मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
c) विनिमय दर में कमी जहां विदेशी मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में भारतीय मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
d) विनिमय दर में कमी जहां घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में कमी आई है

Q.19) Solution (a)

विनिमय दर में वृद्धि का अर्थ है कि घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है। इसे विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) का मूल्यह्रास (Depreciation) कहा जाता है।

इसी तरह, एक लचीली विनिमय दर शासन में, जब विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) की कीमत बढ़ती है, तो इसे विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) का अभिमूल्यन (Appreciation) कहा जाता है।

Q.20) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भरत 22 (Bharat 22), एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जिसमें केवल 22 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (PSU) स्टॉक शामिल हैं
2. ईटीएफ में निवेश कम तरल होते है क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष इक्विटी शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जा सकता है
3. भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के प्रबंधन के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को नियुक्त किया है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.20) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3

असत्य	असत्य	सत्य
ETF एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका उद्देश्य अपने अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक और प्रतिबिंबित करना है। यह उसी स्टॉक में निवेश करने की निष्क्रिय निवेश रणनीति के माध्यम से प्राप्त करता है और उसी अनुपात में जैसा कि वे अंतर्निहित सूचकांक का गठन करते हैं। सूचकांक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी कंपनियों के 22 स्टॉक शामिल हैं, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रणनीतिक होल्डिंग (SUUTI) हैं। उक्त 22 स्टॉक छह क्षेत्रों (मूल सामग्री, ऊर्जा, वित्त, एफएमसीजी, उद्योग और Utilities) में फैले हैं। सूचकांक एकल स्टॉक में अधिकतम 15 प्रतिशत और किसी विशेष क्षेत्र में 20 प्रतिशत निवेश करता है। भारांश प्रतिवर्ष पुनर्संरचित किया जाता है।	ईटीएफ में निवेश अत्यधिक तरल है क्योंकि वे डीमैट खाते के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रत्यक्ष इक्विटी शेयरों जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जा सकता है। साथ ही, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित होने के कारण, उनके पास सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंडों की तुलना में कम व्यय वाले अनुपात होते हैं। भारत 22 ईटीएफ सरकार को एक ईटीएफ में चयनित सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी होल्डिंग संग्रहित करने और एक बार में निवेशकों से विनिवेशित धन जुटाने की अनुमति देता है। यह विशेष रूप से निर्मित S & P BSE Bharat 22 सूचकांक, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित करता है। यह सूचकांक 22 पीएसयू शेयरों और कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों से बना है।	भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ को बनाने, लॉन्च करने और प्रबंधित करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को नियुक्त किया है।

Q.21) प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में बदलना तथा आदिवासियों के लिए बढ़ी हुई आजीविका प्रदान करना है।
2. यह एक बाज़ार संबद्ध जनजातीय उद्यमिता विकास योजना है।
3. इकाई स्तर पर, उत्पादन का एकत्रीकरण 30 स्वयं-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा, जिसे वन धन विकास 'समुह' कहा जायेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.21) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
प्रधानमंत्री वन धन योजना एक बाजार संबद्ध जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जो जंगल की	इसका उद्देश्य प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी और आईटी को उन्नत करके आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और	इकाई स्तर पर, उत्पादन का एकत्रीकरण 10 SHG द्वारा किया जाएगा, जिसमें लगभग 30 सदस्य

संपत्ति का दोहन करके आदिवासियों के लिए आजीविका उत्पादन को लक्षित करता है। कार्यान्वयन केंद्रीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया जाएगा।	कौशल सेट में टैप करना है तथा जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में बदलना है और एक वर्ष में लगभग 45 लाख आदिवासी लोगों को आजीविका प्रदान करना है।	होंगे जो प्रत्येक वन धन विकास 'समुह' का निर्माण करेंगे। क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन और मूल्य संवर्धन सुविधा प्रदान करने तथा प्राथमिक प्रसंस्करण की स्थापना के लिए वन धन विकास केंद्र (VDVKs) की स्थापना की जाएगी।

Q.22) आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है

a) विश्व व्यापार संगठन (WTO)
b) विश्व बैंक
c) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.22) Solution (d)

- आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक व्यापार स्वतंत्रता, कर बोझ, न्यायिक प्रभावशीलता, और इसी प्रकार के अन्य के खिलाफ प्राधिकार क्षेत्र को मापता है।
- आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे व्यापक रूप से संदर्भित सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन, यूएस आधारित थिंक टैंक द्वारा निर्मित है।
- यह 0 (सबसे कम मुक्त) से लेकर 100 (सबसे मुक्त) तक के स्कोर के आधार पर देशों को रैंक देता है।

Q.23) बेलम गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. यह भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है।
2. यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
बेलम गुफा भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरी सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है। मेघालय में सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा KremLiatPrah गुफाएं हैं।	बेलम गुफाएं आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने बेलम गुफाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए बेलम गुफा महोत्सव का आयोजन किया है।

Q.24) जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ठोस पुनर्चक्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को किस रूप में जाना जाता है

a) बार्सिलोना कन्वेंशन

b) लंदन कन्वेंशन
c) हांगकांग सम्मेलन
d) MARPOL कन्वेंशन

Q.24) Solution (c)

- भारत ने हाल ही में जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ठोस पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को स्वीकार किया है।
- यह 2009 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा अपनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहाजों को, जब उनके परिचालन जीवन के अंत तक पहुंचने के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जाए, मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरण के लिए कोई अनावश्यक जोखिम पैदा न करें।

Q.25) निम्नलिखित में से कौन से राज्य इनर लाइन परमिट (ILP) शासन के तहत संरक्षित हैं?

1. मणिपुर
2. मिजोरम
3. मेघालय
4. नगालैंड
5. अरुणाचल प्रदेश

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1, 4 और 5
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 2, 4 और 5
d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.25) Solution (c)

- इनर लाइन परमिट (ILP) एक विशेष परमिट है जिसे भारत के अन्य हिस्सों के नागरिकों को ILP शासन द्वारा संरक्षित राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है।
- यह सीमित अवधि के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है
- यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873 पर आधारित है।
- आईएलपी प्रणाली वाले राज्य: नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम हैं

Q.26) 'रिंग फेंसिंग' (Ring Fencing) शब्द हाल ही में समाचारों में था, यह किससे संबंधित है

a) दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)
b) रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs)
c) अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs)
d) राजस्व प्रोत्साहन

Q.26) Solution (a)

मंत्रिमंडल ने पिछले प्रबंधन / प्रमोटरों द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के सफल नए बोलीदाताओं को "रिंग-फेंस" के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

Q.27) RBI द्वारा 'ऑपरेशन ट्विस्ट' (Operation Twist) के संभावित निहितार्थ क्या हैं?

1. सरकारी बांड की यील्ड (Yields) में गिरावट
2. लंबी अवधि के उधार पर ब्याज दर में कमी
3. बेहतर मौद्रिक प्रसारण

सही कथनों का चयन करें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.27) Solution (d)

RBI के बांड खरीदने से बांड पेपर का मूल्य बढ़ेगा और यील्ड्स (Yields) में गिरावट आएगी। इससे बाजार में दीर्घकालिक तरलता आती है जो दीर्घकालिक उधार पर ब्याज दर को कम करने में मदद करती है।

छोटे स्तर पर तरलता प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अधिक लंबे समय तक नहीं रहेगी। लेकिन लंबी अवधि में तरलता उपलब्ध कराने के इस कदम से मौद्रिक प्रसारण में मदद मिलेगी।

Q.28) 'सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (Universal Service Obligation Fund- USOF)' किसके अंतर्गत आता है

a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
b) संचार मंत्रालय
c) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
d) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

Q.28) Solution (b)

भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 को सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (USOF) को वैधानिक दर्जा देते हुए दिसंबर 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।

भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2004 के रूप में ज्ञात फंड के प्रशासन के नियम 26.03.2004 को अधिसूचित किए गए थे। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (2003, 2006 में संशोधित) के अनुसार, फंड का उपयोग विशेष रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाना है।

यह संचार मंत्रालय के अधीन है।

Q.29) निम्नलिखित में से कौन 'वाशिंगटन सहमति के मूल सिद्धांत' हैं?

1. संपत्ति के अधिकारों का विकास
2. बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दर
3. कम सरकारी उधारी
4. आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण

सही कूट का चयन करें:

a) 1, 2 और 3
b) 2, 3 और 4
c) 1, 3 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.29) Solution (d)

वाशिंगटन सहमति (Washington Consensus) प्रमुख वित्तीय संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी राजकोष द्वारा समर्थित मुक्त बाजार आर्थिक नीतियों का एक सेट संदर्भित करता है। जॉन विलियमसन नाम के एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने 1989 में वाशिंगटन सहमति नाम दिया।

ये मूल रूप से 1989 में जॉन विलियमसन द्वारा निर्धारित दस विशिष्ट सिद्धांत हैं:

- कम सरकारी उधारी। यह विचार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उनके सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उच्च राजकोषीय घाटे से हतोत्साहित करने का था।
- प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास सहायक क्षेत्रों के लिए सब्सिडी से सार्वजनिक व्यय का विचलन।
- कर आधार को व्यापक बनाने और उदारवादी सीमांत कर दरों को अपनाने के लिए कर सुधार नीतियों को लागू करना।
- बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों का चयन करना। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने के बाद (वास्तविक ब्याज दर) ये ब्याज दरें सकारात्मक होनी चाहिए।
- मुक्त रूप से चलायमान मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना।
- मुक्त व्यापार नीतियों को अपनाना। इसके परिणामस्वरूप आयातों के उदारीकरण, टैरिफ और कोटा जैसे व्यापारिक अवरोधों को दूर किया जाएगा।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर नियमों में ढील।
- राज्य उद्यमों का निजीकरण। आमतौर पर, विकासशील देशों में, इन उद्योगों में रेलवे, तेल और गैस शामिल हैं।
- नियमों और नीतियों का उन्मूलन जो प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करते हैं या प्रवेश के लिए अनावश्यक बाधाओं को जोड़ते हैं।
- संपत्ति के अधिकारों का विकास।

Q.30) 'समग्र वैश्विक उत्सर्जन आयोग (OMGE)' के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह पेरिस समझौते के उप-अनुच्छेद 6.4 के तहत निर्धारित है
2. यह उत्सर्जन में शुद्ध कमी को सुनिश्चित करने के लिए कहता है, बजाय इसके कि देश द्वारा बचत वाले अन्य देशों में निर्गत CO2 की भरपाई की जाए।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.30) Solution (c)

क्योटो प्रोटोकाल के तहत कार्बन-ट्रेडिंग व्यवस्था के विपरीत, अनुच्छेद 6.4 बाजारों को "वैश्विक उत्सर्जन में समग्र शमन" (OMGE) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि उन्हें उत्सर्जन में शुद्ध कमी सुनिश्चित करनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी देश में जारी CO2 की भरपाई कहीं और की जाए।